इस सब के कारण हमारे यहां बहुत नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण पोरबंदर और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में dewatering की भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। वहां एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी गई थीं। भारतीय वायुबल और भारतीय वायुसेना को भी वहां राहत के काम के लिए भेजा गया था। जामनगर जिले के लालपुर में 17 जुलाई को करीबन एक दिन में 800 मिली मीटर से ज्यादा बारिश हुई है। वहां 20 इंच से ज्यादा बारिश एक साथ हो गई है, जिससे वहां के 50 से ज्यादा गांव अतिवृष्टि के कारण ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। इससे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। वहां एसआरपी और एनडीआरएफ के विशेष दलों को भी भेजा गया है। वहां से करीबन 7,800 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। वहां पर करीब दो हैलीकॉप्टर्स द्वारा 70,000 से भी ज्यादा फूड पैकेट्स के वितरण का कार्य राज्य सरकार को करना पड़ा है। इस तरह इस natural calamity की दृष्टि से वहां पर इसकी तुरंत घोषणा होनी चाहिए। वहां गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलिफ मिले, ऐसी हमारी डिमांड है ...**(समय की घंटी)**... मैं इस सभा में आप सब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : इससे बहुत सारे लोग एसोसिएट कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करती हूं।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री परिमल नथवानी (झारखंड) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

Metro rail services from Tollygange to Garia in Kolkata

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is tearnt that the hon. Minister for Railways has decided to inaugurate the Kolkata Metro Railway Services extension portion between Tollygange to Garia on 23rd August, 2009. The announcement to this effect has already been made by the Minister herself without consulting the Government of West Bengal, which is sharing 33 per cent of the total cost of this project. It is a fact that the people of Kolkata are demanding the extension of the metro services from Tollygange to Garia and the completion of project is a very welcome step. The Government of West Bengal extended its full cooperation to fulfill the demand of people and up to 31st March spent so far Rs.221.46 crore for this project. Even the Government of West Bengal shares the 33 per cent of the escalated cost of this project. Initially, the project cost was Rs.696 crore, then subsequently revised to Rs.907.69 crore and then further revised to Rs. 1032.76 crore. The 33 per cent cost is borne by the State Government. The State Government also arranged to rehabilitate 500 families which were residing on the banks of Tolly Nallah. Not only that, the State Government allotted land for construction of metro rail services without any cost. But the hon. Minister for Railways simply forgot all these facts before declaring her inaugural programme as a pooja gift. Even in hurry, she appeared to be forgotten that the stretch of metro railway is yet to

be cleared by the Commissioner of Railway Safety which is a mandatory one. Sir, we request the Government to intervene and not to repeat such things.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I associate with the Special Mention made by the hon. Member.

Reservation for 'Gujjars' of Rajasthan

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपसभापति महोदय, मैं एक अत्यंत संवेदनशील इश्यू की ओर आपका और ध्यान सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

राजस्थान मे गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ी गंभीर और विस्फोटक स्थिति बन गई है। मैं यहां उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, जो देश और प्रदेश को पिछली बार इसके कारण क्षति हुई थी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, उसे यह जानकारी होगी कि पिछली बार विधान सभा मे सर्वसम्मति से, जिसमें रूलिंग पार्टी भी थी और अपोजिशन भी था, वह अपोजिशन जो कि आज सरकार में बैठा है, यह तय किया गया था कि गुर्जरों को 5 प्रतिशत और सामान्य श्रेणी के अति निर्धन लोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इस पर लम्बी बहस हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष की भी पूरी सहमति थी। महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय विधि विभाग से भी इसकी सहमति ली गई थी और जो संशोधित प्रस्ताव आया, वह विधान सभा में सर्वसम्मति से पास किया गया।

किन्तु आज ऐसा लगता है कि सर्वसम्मत प्रस्ताव पास होने के बाद भी उस पर राजनीति की जा रही है। वे लोग जो उस वक्त विपक्ष में थे, आज सरकार में बैठे हैं, उस समय कहा करते थे कि सामान्य रूप से इसका हल हो जाएगा। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर तत्कालीन सरकार ने एक आयोग का गठन किया था - श्री जसराज चोपड़ा आयोग, और उसने भी यह कहा था कि निश्चित रूप से इस बात को ...**(व्यवधान)**...

डा. प्रभा ठाकुर : सर, मैं कहना चाहती हूं कि पांच साल ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please, don't intervene in between.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरा समय ले रही है। ...**(व्यवधान)**...

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : पांच साल रहे, इन्होंने क्या किया ...**(व्यवधान)**... इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्रभा ठाकुर जी, आप क्यों खड़ी हो रही हैं। ...**(व्यवधान)**... बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे मेरा समय ले रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा. प्रभा ठाकुर : इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्रभा ठाकुर जी, आप सदन का टाइम ...**(व्यवधान)**... आपको जवाब देने के लिए नहीं कहा गया है। ...**(व्यवधान)**... आप मैम्बर को बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया, विपक्ष की सहमति हो गई ...**(व्यवधान)**... आज जब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है तो कहा जा रहा है कि इस पर दस्तखत नहीं किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि महामहिम इस पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे हैं, वे जाने या भगवान जाने। किन्तु, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले पर केन्द्र सरकार इंटरवीन करे, तुरंत उस पर निर्णय ले, अगर निर्णय नही लेगी तो इसका परिणाम क्या होगा, यह हमने पिछली बार देखा है।